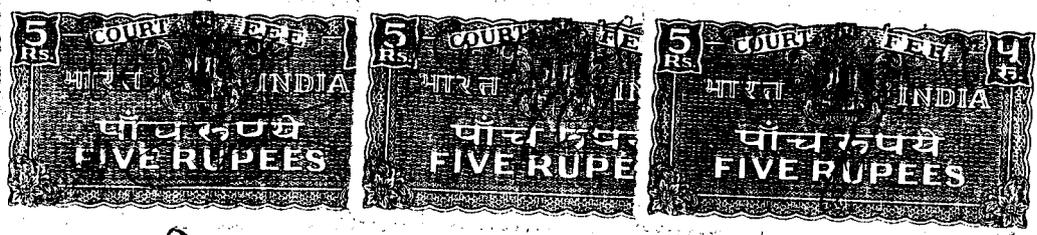


माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, म०प० कैम्प रीवा ।

Handwritten notes in the left margin, including a date '16-2-41' and some illegible text.



A - 385-II/2001.

- 1. सम्प्रति कुमार पिता सरजू तभी निवासी ग्राम हुड़बा, तहसील-
- 2. बंशराम पिता रामाश्रय रायपुर कर्चुल्लयान, जिला रीवा
- 3. दुरधीट्या पुत्री रामीस्था म०प० ।
- 4. रामनारायण पिता बृजभान
- 5. अंभमान पिता बृजवासी

अधीलाधी/आबेदक गण ।

खाम

- 1. रामराजीवन पिता काशीनाथ ✓ तमस्त निवासी ग्राम हुड़बा,
- 2. राजभान पिता काशीनाथ ✓ तहसील रायपुर कर्चुल्लयान,
- 3. मु० कलावती पुत्री काशीनाथ ✓ जिला रीवा म०प० ।
- 4. पुल्लसुजा पत्नी रामसुन्दर ✓
- 5. भूमेन्द्र पुत्र रामसुन्दर ✓
- 6. रामभुवन पिता रामसुन्दर ✓
- 7. सन्तोष पिता रामसुन्दर ✓
- 8. ललुआ पिता रामसुन्दर, नाबालिग जीरस बली माँ पुल्लसुजा

उत्तरवादी/अना०

- 9. रामशरण पिता रामसखा तमस्त निवासी ग्राम हुड़बा, तहसील रम
- 10. तेजभान पिता रामसखा रायपुर कर्चुल्लयान, जिला रीवा -
- 11. बृजवासी पिता रामसखा म०प० ।
- 12. बृजलाल पिता बैजनाथ
- 13. भवानदीन पिता बैजनाथ
- 14. राजेन्द्र पिता बैजनाथ

रेस्था०/आबेदक गण ।

:: 2 ::

प्रथम अपील विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त
महोदय, रीवा संभाग रीवा । श्री भानु प्रकाश -
सिंह, रा.प्र.क्र. 33/पुनर्स्थापना/2000-2001,
आदेश दिनांक 19.1.2001 .

अपील अन्तर्गता धारा - 35(4) म.प्र.भू.रा.
संहिता - 1959 ई० ।

M

72040

20

मिल

1959

मिल/91-22

35(4)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 06-06-17 | <p>उभय पक्ष के अभिभाषकों के पूर्व पेशी पर तर्क सुने जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 33/2000-01 पुर्न. में पारित आदेश दिनांक 19-1-2001 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(4) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों अनुसार तथा उपलब्ध अभिलेख अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील क्रमांक 564/1991-92 प्रस्तुत की थी, जिसे अपीलार्थीगण एवं उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर आदेश दिनांक 2-11-2000 को निरस्त कर दी गई। अपीलार्थीगण ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(3) के अंतर्गत अदम पैरबी आदेश को निरस्त करने हेतु आवेदन दिनांक 1-1-2001 प्रस्तुत किया जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 19-1-2001 से अमान्य कर दिया। इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ उपरोक्त पद 2 में दिये गये विवरण एवं अपील मेमो में अंकित तथ्य तथा अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 33/2000-01 पुर्न. के अवलोकन पद स्थिति यह है कि पेशी 2-11-2000 को अपीलार्थी के</p> | <p><i>(Signature)</i> 25</p> |

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

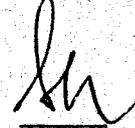
प्रकरण क्रमांक 385-दो/2001 अपील

जिला- रीवा

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|--------------|--|--|
| | <p>अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त किया गया तथा दिनांक 1-1-2001 को अर्थात् लगभग 59 दिवस के अंतर से आवेदन आने पर पुर्नस्थापन आवेदन अमान्य किया गया है जबकि पुर्नस्थापन आवेदन हेतु 30 दिवस की समयावधि नियत है। इस प्रकार लगभग 29 दिवस के विलम्ब को अपर आयुक्त ने क्षमा नहीं किया है जबकि अपीलार्थीगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष म्याद अधिनियम 1963 की धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर विलम्ब का कारण दर्शाया है। न्यायदान की दृष्टि से माना गया है कि अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिये तथा मामले में गुणागुण पर विचार कर न्यायगत निर्णय देना चाहिये, किन्तु विचाराधीन प्रकरण में म्याद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने भलीभाँति विचार नहीं किया है तथा न ही आदेश दिनांक 19-1-01 में तथ्यों की विवेचना की है कि उन्होंने म्याद अधिनियम के आवेदन में दिये गये विवरण को क्यों सही नहीं माना है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 19-1-2001 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।</p> <p>4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 33/2000-01 पुर्न. में पारित आदेश दिनांक 19-1-2001 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपील क्रमांक</p> | |

A - 985 - II / 2001 सीवा

564/1991-92 को पुर्नजीवित करते हुये समस्त हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत् सूचना जारी करें तथा अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्राप्त कर मामले का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।


सदस्य

M